SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : It is a continuous process. (*Interruptions*)

SHRI N.E. BALARAM : We can pass on to the next question. There is no use. (*Interruptions*)

SHRI VIREN J. SHAH : What is the point in having Question Hour. It is ridiculing the House. (*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY : Madam one supplementary.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We have spent enough time on this. Question No. 162. Shri Suresh Pachouri. (*Interruptions*)

Voluntary Organisations for Promoting Female Literacy

*162. SHRI SURESH PACHOURI† :
SHRI IQBAL SINGH :

Will the MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that States having higher female literacy rates have lower birth rates;

(b) if so, what steps are being taken to increase female literacy;

(c) whether voluntary organisations have also been associated with the project; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (d) A statement is laid on the table of the house.

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Suresh Pachouri.

Statement

Voluntary Organisations for Promoting Female Literacy

(a) Yes, sir. In general, States having higher female literacy rate have lower birth rate.

(b) The steps taken by the Govt. to increase female literacy include measures to achieve Universalisation of Elementary Education (UEE) with stress on girls' education, setting up of Non-Formal Education (NFE) Centres for the children in the 6-14 age-group and Adult Education programmes through the National Literacy Mission (NLM) with focus on female literacy. The NLM aims at imparting functional literacy to 80 million illiterates in the 15-35 age-group by 1995. The dominant strategy under the Mission is Total Literacy Campaigns (TLCs) which have been launched in 189 districts in the country covering about 42 million illiterates. Majority of the learners in these campaigns are women. As a matter of fact, the major thrust of all the programmes of UEE, NFE and NLM is promotion of literacy among women and among members belonging to SCs and STs, particularly in the rural areas, as it is amongst them that the incidence of illiteracy is the maximum.

(c) & (d) There are no speical schemes for exclusively promoting female literacy through voluntary organisations. However, voluntary organisations have been associated in all the 189 TLCs in progress in various parts of the country under the NLM. Besides, 49 Voluntary Agencies have been sanctioned TLC projects for making 12,80,201 illiterates, including 7,43,827 women, literate under the Central Scheme of Assistance to Voluntary Agencies in Adult Edu-

cation. This scheme emphasises on participation of women in literacy programme by extensive involvement of women as volunteer instructors and learners and by requiring the Voluntary Agencies to ensure that learning centres are located and their timings fixed at the convenience of women learners. Further, under the centrally sponsored scheme of Non-Formal Education (NFE), assistance is also provided to VAs for running NFE centres for the children in 6-14 age group. At present, about 23,000 NFE centres are being run by VAs. However, no VA is running any NFE centre exclusively for girls.

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, यद्यपि माननीय मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि साक्षरता अभियान का सीधा संबंध जनसंख्या और गरीबी से है । महोदया, 1991 के आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि जहां महिलाओं में साक्षरता कम है वहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, जैसे अगर 1991 के सेंसस के हिसाब से महिलाओं का लिटरेसी रेट देखा जाए तो उड़ीसा में वह 34.4 परसेंट रहा, आंध्र में 33.71 परसेंट, मध्य प्रदेश में 28.39 परसेंट, उत्तर प्रदेश में 26.02 और राजस्थान में 20.84 परसेंट रहा, वहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन स्थानों पर ज्यादा रहा । इसलिए यह जरूरी है कि महिलाओं में साक्षरता अभियान ज्यादा तेजी से चलाया जाए क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां कि 28.39 परसेंट फीमेल लिटरेसी रेट है वहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.37 परसेंट है, उत्तर प्रदेश में जहां . . .

उपसभापति : सवाल पूछिए ।

श्री सुरेश पचौरी : तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि महिलाओं में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और मेरे प्रश्न का "बी" पार्ट यह है ।

उपसभापति : "बी" पार्ट सैकंड सप्लीमैंटरी में पूछ लीजिए ।

कुमारी शैलजा : मैडम, माननीय मेंबर ने ठीक कहा है कि अमूमन यही है कि जहां पर फेमिली लिटरेसी रेट लो है वहां पर बर्थ रेट भी हाई है । स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन तकरीबन ऐसा देखा गया है रेट में । हमने फीमेल लिटरेसी के लिए काफी स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक लिटरेसी की बात है यह स्टेट और सेंटर दोनों का एक ज्वाइंट एनडेवर है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि लिटरेसी रेट ज्यादा हाई किया जाए हमारे देश में और खासकर महिलाओं में । इसके लिए अनेक कार्यक्रम स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी हैं । स्टेट लेवल पर तो जैसे कई स्टेट्स में "प्लस टू" लेवल पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त कर दी गयी है, कई जगह स्कॉलरशिप्स हैं, कई जगह फ्री यूनिफार्म्स और किताबें हैं । इसके अलावा हमारी जो नेशनल पॉलिसी है, प्रोग्राम आफ एक्शन है, उसमें भी एम्फेसिस फीमेल लिटरेसी पर दिया गया है और सेंट्रल स्कीम्स बहुत हैं । इसके तहत जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, उसमें भी हमने यह प्रावधान किया है कि जो दो टीचर्स एक स्कूल में रखे जाएंगे उनमें से कम-से-कम एक जरूर महिला हो । इसके तहत बताना चाहूंगी कि यहां पर आज के दिन हमारे पास 69926 टोटल टीचर हैं, उसमें से 57 परसेंट महिलाएं हैं, जो कि 50 परसेंट के प्रावधान से ज्यादा ही हैं । इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम हमारे पास हैं, जैसे नॉन फोर्मल एजुकेशन सेंटर की बात है, वहां भी हम ज्यादा प्रोत्साहन लड़कियों के सेंटर को देते हैं, जिसमें हमारे पास आज के दिन 2,45,000 नान फोर्मल एजुकेशन सेंटर हैं, उनमें से 82,000 सेन्टर लड़कियों के लिए ही हैं । इसी तरह से, यहां तक नवोदय विद्यालय की बात है, वहां पर भी हम समय तकरीबन 28 प्रतिशत लड़कियां दाखिल की हैं । इसके अलावा जो यूनिवर्सलाइजेशन आफ एलीमैन्टरी एजुकेशन है, वहां भी लड़कियों की ओर खास ध्यान दिया गया है । और जो स्कीम, टोटल

लिटरेसी, पूर्ण साक्षरता अभियान की, शुरू की हुई है उसमें भी लार्जर ग्रुप महिलाओं का ही रखा गया है। और भी हैं, जैसे जेन्डर सेंज़िटाइजेशन कोई भी कार्यक्रम हम लाते हैं खासकर के शिक्षा की तरफ से, शिक्षा डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसमें जेन्डर सेन्ज़िटाइजेशन की ज्यादा जरूरत है। एक नई स्कीम हमने शुरू की है गर्ल्स होस्टल स्कीम, जिसके लिए प्रावधान रखा गया है दो करोड़ का इस प्लान में, जो कि सेकेन्डरी लेवल स्कूल में होस्टल के लिए दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है इसमें भी लड़कियों के लिए काफी कुछ हम करने जा रहे हैं। यह सब बातें तो मैंने कही है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश है, इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगी कि जितना काम होना चाहिए हमारे देश में, उतना नहीं हुआ है। इसके लिए पूरा समाज और सब लोग, वालयुंटरी एजेंसी और गवर्नमेंट, सब लोग मिलकर ही यह चलाएंगे तो ही यह अभियान हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें एक जो आशा की किरण हमें नजर आती है, वह यह है कि पूरे दशक (1981–1991) में जो लिटरेसी रेट बढ़ा है, उसमें मेल 7.76 परसेंट था और फीमेल लिटरेसी रेट जो था 9.54 परसेंट था, जोकि ज्यादा है।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, ...

उपसभापति : इतना तो जवाब दे दिया, अब उसमें कुछ रहा नहीं।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न .... (व्यवधान) ....

THE DEPUTY CHAIRMAN : Next supplementary. (*Interruptions*) I think we can move on to another question. She has given a very elaborate answer. मुबारकबाद दे दीजिए।

श्री सुरेश पचौरी : वह तो मैंने पहले ही कह दिया था। महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि पिछले दिनों से लगातार यह शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ कम्युनल आर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, वह कुछ इस प्रकार के पाठ्यक्रम चला रही हैं, जिससे कि धार्मिक उन्माद भड़के। नेशनल लिटरेसी मिशन का गठन वर्ष 1988 में हुआ था, जिसमें लक्ष्य यह था कि वर्ष 1995 तक 80 मिलियन बच्चों को साक्षर कर दिया जाएगा। जब इस प्रकार की शिकायतें मिलीं कि कुछ कम्युनल आर्गेनाइजेशन इस प्रकार के पाठ्यक्रम अपनी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से पढ़ा रही हैं और इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तो इसके लिए जुलाई, 1992 में मंत्रालय ने फैसला लिया कि स्क्रीनिंग कमेटी का गठन स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाएगा। तो राज्यों में, विशेष रूप से मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर इन स्क्रीनिंग कमेटी का गठन क्या मंत्रालय के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हो चुका है? और, अगर नहीं हुआ है तो क्या मंत्रालय इस प्रकार से राज्यों को निर्देशित करेगा कि इन राज्यों में इस प्रकार की स्क्रीनिंग कमेटी गठित हो जाए? मेरा, दूसरा पाठ, यह है कि जो बीच में, बच्चे पहली क्लास से आठवीं क्लास तक, पढ़ाई छोड़ देते हैं, विशेषकर बच्चियां, उनका परसेंटेज मध्यप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा है, उस परसेंटेज को कम करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कुमारी शैलजा : मैडम, जो पहला सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जो यह कमेटी कांस्टीट्यूट हुई थी वह किताबों के बारे में नहीं थी कि किस तरह का पाठ्यक्रम होगा। यह सिर्फ वालयुंटरी एजेंसी जो है, उनको जो हम सेंक्शन करते हैं उसके बारे में थी, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए थी। इसमें यह बात भी उठी थी कि कई राज्यों ने यह कांस्टीट्यूट नहीं की है।

श्री सुरेश पचौरी : कौन कौन से हैं।

कुमारी शैलजा : मैडम, मध्यप्रदेश उन में से एक है। उन्होंने स्टेट लेवल की की थी,

लेकिन कन्फोरमिटि में नहीं थी, जो हमने गाइड-लाइन सेंटर से दी थी, उसके तहत नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की वहां पर नहीं हुई। इसके बारे में मैं यह कह सकती हूं कि हम इन राज्यों को दुबारा से यह गाइडलाइन भेजेंगे और दुबारा उनको कहेंगे कि स्क्रीनिंग कमेटी, जितनी जल्दी हो सके, उसको कांस्टीट्यूट करें। यहां तक दूसरा सवाल है इनका, ड्राप आऊट रेट का, ड्राप आऊट रेट काफी हाई है। इससे मैं सहमत हूं खासतौर पर लड़कियों के लिए, लेकिन इसके लिए भी मैं वही कहूंगी, जो मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा है कि अलग-अलग स्कीम हम जो लाए हैं तो उसमें यह भी एक कम्पोनेन्ट उसका है कि ड्राप आऊट रेट किस तरह से उसका रेड्यूस किया जाए। इसीलिए महिलाओं को भी लाया जाता है इस स्कीम में, ताकि उनमें इसके बारे में एक जागरूकता लाई जा सके कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में रखना चाहिए।

कल्याण मन्त्री (श्री सीता राम केसरी) : क्वैश्चन पचास हजार का था, जवाब एक लाख का।

SHRIMATI KAMLA SINHA : Madam Deputy Chairman, I would like to ask the Minister one very small and direct question. We know there is a proverb that if you educate a man you educate a person but if you educate a woman you educate a family. So, in that context I would like to ask this question. We know there is population explosion going on in our country especially in the Hindi belt. So, what special schemes is the Government adopting for female literacy with special emphasis on the Hindi belt ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : She gave a complete report on the whole project in the whole country. The same applies to that. I don't think there is anything specific. The question she has answered.

SHRIMATI KAMLA SINHA : But I would like to know what is being done in Bihar and Uttar Pradesh. We do not find any effect of the project there.... *(Interruptions)*

KUMARI SELJA : We do have projects for these States also. There is nothing specific for the Hindi belt. We do have projects like Mahila Samakhya and other projects which are there in States like U.P., for instance. But I may add that all these projects that we have and all these Central schemes are on female literacy.

THE DEPUTY CHAIRMAN : There is nothing left in this question, Next question.

श्री मूल चन्द मीणा : क्वैश्चन नं० 163.

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसमें एक ही सप्लीमेंटरी हुआ ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : We should go ahead. She gave a full answer. Let us have more questions.

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसमें सवाल पूछना है। (**व्यवधान**)

डा० मुरली मनोहर जोशी : यह मालूम पड़ता है, आप महिलाओं का संरक्षण करती हैं। (**व्यवधान**)

उपसभापति : बोलिए मंत्री जी। (**व्यवधान**)

राजस्थान के लिए सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

*163. **श्री मूल चन्द मीणा† :**
श्री बी० नारायणसामी .

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

†सभा में यह प्रश्न श्री मूलचन्द मीणा द्वारा पूछा गया।